शहर की जनता से रिश्ता
छत्तीसगढ़ का पहला मिड-डे अखबार

योगी सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के 35 लाख लोगों को राहत देने के लिए एक हजार रुपए की मदद का ऐलान किया है, 3500 करोड़ रुपए की यह रकम असंगठित क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए नाकाफी है, जो नोटबंदी के बाद कोरोना के कहर का शिकार हो रहे हैं। कनिका ने जिस ताज होटल में पार्टी की थी, उसे स्थानीय प्रशासन ने बंद करवा दिया है। कानपुर और लखनऊ में कनिका कपूर जिन जगहों पर गईं, वहां पर बड़े पैमाने पर जनता के पैसों से लॉक डाऊन हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में राज्यों के साथ केंद्र एक समन्वित नीति अपनाए।

बॉलिवुड ने दिखाई है उम्मीद की किरण

अविनाश दास

इधर कुछ दिनों से अभिनेता कार्तिक आर्यन के विडियो संदेश वायरल हो रहे हैं। इनमें वह कोरोना वायरस के प्रति लोगों की लापरवाही पर खीझ दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर संदेशों की लंबी श्रृंखला है, जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि वे क्या करें क्या न करें। खास जोर इस पर है कि जहां तक हो सके, सबको अपने घर में ही रहना चाहिए। सुविधा संपन्न लोगों के लिए एकांत एक लग्जरी है, लेकिन उनका क्या जो दिन के हिसाब से कमाते हैं और अपने परिवार के लिए रोजी-रोटी जुटाते हैं?

साधनहीनों की बात : महात्मा गांधी हमेशा कतार में खड़े अंतिम आदमी की बात करते थे। लेकिन आज की सरकारें, धनसंपन्न लोग और सेलिब्रिटीज 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' की चादर झाड़ कर निश्चिंत हो जा रही हैं। कोई भी यह नहीं सोच रहा कि इन सुझावों पर अमल करना उन लोगों के लिए कितना मुश्किल साबित होने जा रहा है जिनके पास साधन नहीं हैं। इन मुश्किलों को आसान बनाने के उपायों पर कोई बातचीत फिलहाल सार्वजनिक मंचों पर नहीं दिख रही। मगर ऐसा नहीं है कि कहीं इस दिशा में कोई कोशिश ही नहीं हो रही है।

जैसी उम्मीद की किरण केरल की सरकार से दिखती है, जिसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बीस हजार करोड़ रुपये के पैकेज का एलान किया है, कुछ वैसी ही रोशनी बॉलिवुड की ओर से भी तब दिखाई दी, जब चर्चित फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा ने बॉलिवुड के कुछ संवेदनशील डायरेक्टरों से अपील की कि वे उन लोगों की मदद के लिए आगे आएं, जिनकी कमाई का जरिया रोज का श्रम है। विक्रमादित्य मोटवानी और अनुराग कश्यप से लेकर हंसल मेहता, राहुल ढोलकिया, निखिल आडवाणी और अनुभव सिन्हा जैसे निर्देशक इस अपील के बाद सक्रिय हुए।

मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में लाखों की तादाद में डेली वेज वाले श्रमिक हैं। इनके लिए फंड जुटाना और एक-एक तक मदद पहुंचाना आसान नहीं। इसके लिए सारी फिल्म निर्माता कंपनियों का साथ होना जरूरी है, ताकि सूची बनाने में आसानी हो। प्रोड्यूसर्स असोसिएशन इसके लिए आगे आया है। बड़ी बात यह कि ये लोग गंभीरता से इस काम में लगे हुए हैं। सुधीर मिश्रा ने यह अपील ट्विटर के जरिये 15 मार्च को की थी। उसके बाद ही यह पहल शुरू हुई और फिर आगे बढ़ती गई। मेरे पास यह सूचना नहीं है कि कितने लोगों तक मदद पहुंची, लेकिन पहुंचनी शुरू हो गई है, इस बात की पक्की सूचना है।

आपदा की स्थिति में सिनेमा से जुड़े लोगों की यह पहल इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि जिन्हें देश हीरो मानता है, उनके नागरिक दायित्व भी होते हैं। इसी दायित्व के तहत वे सरकारों के खिलाफ बोलते हैं और पार्टियों के स्थायी वोटर्स की नाराजगी मोल लेते हैं। इससे देशवासियों के एक हिस्से में ऐसी धारणा बनती है कि फिल्मी दुनिया की बड़ी-बड़ी हस्तियां महज पब्लिसिटी के लिए सरकार विरोधी बयान जारी करती हैं। ऐसे में आज के संकटपूर्ण हालात में की गई यह गंभीर और सामयिक पहल भारत में सिनेमा से जुड़े लोगों की विश्वसनीयता बढ़ाएगी। साल 2011 में एक अमेरिकी फिल्म 'कंटेजिएन' (संक्रमण) आई थी, जिसकी कहानी कुछ उसी तरह के हालात में बनती है, जैसे आज इटली, ईरान और खुद भारत में भी दिखाई पड़ रहे हैं। फिल्म में अपनों को बचाने की कवायद करते हुए लोग हैं और सरकारी प्रयासों के भीतर एक कांस्पिरेसी थियरी का पीछा करता हुआ स्वतंत्र पत्रकार है। मानवता के लिए अपनी निजी सुरक्षा से समझौता करने वाले बड़े लोगों की कोई कथा इस फिल्म में शामिल नहीं है। अलबत्ता छोटे लोगों की एक ऐसी कथा जरूर है, जिसमें एक लेडी डॉक्टर को संक्रमण हो जाता है और वह मरीजों की भीड़ में शामिल हो जाती है। चीन के वूहान शहर के एक अस्पताल में जब कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जान बचाने में लगे डॉ फंग यिनह्वा की मौत हो गई तो 'कंटेजिएन' की उसी युवा डॉक्टर की याद आ गई। हमारे यहां भी हर किसी को एकांत में रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन डॉक्टर्स की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाइए तो आपको उनकी तस्वीर के साथ एक टैग लाइन मिलेगी, 'आइ कैन नॉट स्टे होम, आइ एम अ हेल्थकेयर वर्कर।' (मैं घर में नहीं रह सकता, मैं एक स्वास्थ्यकर्मी हूं।) बॉलिवुड में लोग जरूर घरों में बैठ गए हैं और सारा कामकाज ठप हो गया है, लेकिन इससे प्रभावित होने वाले मजदूरों के लिए निर्माता-निर्देशकों की फौज जिस तरह से एकजुट हुई है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। यहां चमकते हुए सितारों की लौ जब मद्धिम होने लगती है, तो लोग उन्हें भी भूल जाते हैं। ओपी नैयर जैसे बड़े संगीतकार को अपने आखिरी वक्त में अकेलेपन का दुख झेलना पड़ा। इंडस्ट्री की बेवफाई से वे इस कदर खफा थे कि उन्होंने कह दिया कि उनकी अंतिम यात्रा में कोई शरीक न हो। मुंबई से दूर ठाणे की एक बहुत छोटी सी जगह नालासोपारा में उनके आखिरी दिन बीते। ऐसे किस्सों की लंबी फेहरिस्त है।

रचना में भी दिखे : एक फेहरिस्त ऐसे किस्सों की भी है जिसमें लोगों ने लोगों की मदद की है। लेकिन मदद के दौरान मजदूरों को भी पूछा गया हो, ऐसे किस्से बॉलिवुड में नहीं सुनने को मिलते। एक्सट्राज और सहायक टेक्नीशंस के बारे में कभी कोई बात नहीं होती। आज जब फिल्म इंडस्ट्री में लोग अपनी नागरिकता को लेकर ज्यादा संवेदनशील हो रहे हैं, वायरस की वजह से पैदा हुई शट डाउन की स्थिति में सबसे कमजोर लोगों के हाथ थामने की पहल हुई है तो यह कोई छोटी बात नहीं है। हम जो करते हैं, उसका असर हमारी रचना, हमारे सृजन पर भी पड़ता है। उम्मीद करें कि आने वाला वक्त मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए और ज्यादा मानवीय होगा।

कोरोना से बचाव के लिए कनिका जैसों पर लगे 'रासुका'

विराग गुप्ता

कोरोना वायरस के कहर से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई जनता कर्फ्यू की अपील का पूरे देश में पालन होगा। कोरोना के बारे में सच से ज्यादा अफवाह और विवाद हैं लेकिन इस बात पर सभी लोग एकमत हैं कि महामारी का यह वायरस विदेशों से भारत में आ रहा है। बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर की करतूत से देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अनेक मंत्रियों के साथ दूसरे राज्यों के सांसद भी अब संदेह के दायरे में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस और सी.एम.ओ. द्वारा कनिका कपूर के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 188, 269 और 270 के तहत चार एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई हैं। हल्की धाराओं

में दर्ज ऐसे मामलों में तुरंत जमानत मिलने के साथ अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। कनिका कपूर जैसी गैर जिम्मेदार सैलीब्रिटीज की मनमौजी फ्रीडम के लिए करोड़ों जनता के मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है। यू.पी. के मुख्यमंत्री अपनी प्रशासनिक सख्ती के लिए मशहूर हैं। कनिका कपूर के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वह बिग बॉस के प्रतिभागियों की तरह इस विवाद का फायदा उठाकर और ज्यादा चर्चित और सफल हो जाएंगी। कनिका कपूर जैसे कई और भी हैं। कनिका के संग पार्टी करने वाले पूर्व सांसद अकबर अहमद डम्पी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। सैलीब्रिटीज की पार्टी में सभी राजनीतिक दलों के नेता सर्वधर्म समभाव से शामिल होकर जनसेवा की नई मिसाल पेश करते हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री समेत कई लोगों का कोरोना टैस्ट अभी भले ही नैगेटिव आया हो, लेकिन इस वायरस का प्रभाव कई बार दो हफ्ते बाद ही दिखता है। कनिका कपूर की पार्टी में गए भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अब एकांतवास में चले गए हैं, लेकिन उनकी लापरवाही से अनेक सांसद और राष्ट्रपति संक्रमण के दायरे में आ गए हैं। टी.आर.एस. के विधायक और कई अन्य राजनेताओं ने भी ऐसा ही जनविरोधी आचरण किया है, जिसे देखकर कई दूसरे लोग भी अस्पतालों और एयरपोर्ट से भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता की मलाई के लिए व्याकुल नेताओं ने तो भीड़ के साथ शक्ति प्रदर्शन करने के बाद रात में विधायकों के साथ सामूहिक डिनर भी कर लिया। देश के प्रधानमंत्री जब संकल्प और संयम की बात कर रहे हों उस समय राजनेताओं और सैलीब्रिटीज का ऐसा बर्ताव देश विरोधी ही माना जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए राजेश कवि ने क्या खूब लिखा है,''देश की अच्छी हिफाजत कर रहे हो, खेत विधवा का समझकर चर रहे हो।'' कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर धरना-प्रदर्शन और तोड़-फोड़ करने वाले दंगाइयों के खिलाफ योगी सरकार ने उनके पोस्टर लगवाकर, भारी जुर्माना वसूलने की कार्रवाई शुरू की थी। सार्वजनिक तोड़-फोड़ में सिर्फ सम्पत्ति का ही नुक्सान होता है, जिसकी भरपाई आसान है लेकिन आपराधिक लापरवाही से कोरोना वायरस के विस्तार करने को समाज और देश दोनों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ माना जाना चाहिए। कोरोना के संक्रामक वायरस को जाने-अनजाने बढ़ाने वाले लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझें, इसके लिए जरूरी है कि कनिका कपूर जैसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक दंगाइयों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) और गैंगस्टर एक्ट लगाया। उसी तर्ज पर कनिका कपूर के खिलाफ भी यदि कार्रवाई हो तो अमीरजादों की बेशर्मी का लबादा बेनकाब हो जाएगा। विदेशों से आयातित यह संकट आगे चलकर और गहराना ही है। केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अल्पकालिक रोक लगा दी है।

कोरोना वायरस से निपटने में हम कितने सक्षम

खुशबू गुप्ता

कोरोना वायरस (कोविड19) आपदा संपूर्ण विश्व के लिए एक चुनौती बन कर उभरी है। इस संकट की भयावहता और इससे उत्पन्न चिंताओं को महसूस कर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। संक्रमण के घातक प्रकोप, भयावह स्थिति और सबसे निराशाजनक उसके प्रति चौंकाने वाली लोगों की अकर्मण्यता पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 'यदि सभी देश अपने नागरिकों की जांच, उपचार, पृथक्करण कर लोगों को जागरूक और सक्रिय करें तो वे इस वैश्विक महामारी का रुख मोड़ सकते हैं।' विश्व के कई देशों ने कोरोना से निपटने के लिए कुछ बड़े और कठोर फैसले किए हैं, जिसमें नागरिकों की भूमिका अहम रही है। भारत विकास के लिए प्रयत्नशील देश है और हमारे लिए यह संकट सामान्य बात नहीं है।

इसमें कोई संशय नहीं कि बिना नागरिकों के सहयोग के इस महामारी का मुकाबला कर पाना मुश्किल है। इसलिए देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से जारी सभी परामर्शों और दिशा-निर्देशों का पालन करें। कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन पर अमल कर सहयोग करें। यह कोरोना से निपटने में यह जन भागीदारी काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है। जैसे वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि भीड़ वाले स्थानों पर जाने से एकदम बचा जाए। लेकिन अभी यह देखने में आ रहा है कि लोग इस तरह के संकल्प और संयम को महत्त्व नहीं दे रहे। देश में कई मामले तो ऐसे सामने आए हैं जिनमें लोगों ने जरूरी जानकारियां छिपाईं और उनकी यह लापरवाही दूसरों के लिए संकट का बड़ा कारण बन गई।

कोरोना जैसी महामारी के संकट से निपटने में सामाजिक संगठनों की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण हो सकती है। समाज के समझदार जागरूकता लाने के काम में बड़ी मदद कर सकते हैं। इस महामारी के प्रकोप से सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय स्वच्छता है। सामाजिक संगठनों को इसे 'व्यावहारिक परिवर्तन' के कार्यक्रमों में शामिल कर इसके बारे में नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। हालांकि भारत में स्वच्छता अभियान के लिए प्रयास कम नहीं हुए हैं, लेकिन साफ-सफाई के प्रति लोगों में आज भी सजगता का अभाव देखने को मिलता है और वह भी बड़े पैमाने पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी आवश्यकता पर जोर दिया है। कोरोना संक्रमण जिस तरह का भयावह रूप धारण कर गया, उसके पीछे सरकारों की असफलता तो बड़ा कारण है ही, आमजन की लापरवाही ने भी इसे बढ़ाया है। इससे बचने का उपाय चिकित्सकीय से ज्यादा सामाजिक एवं व्यावहारिक वातावरण पर निर्भर करता है। इसलिए स्वैच्छिक संगठन लोगों को इस महामारी के खौफ से निकाल सकते हैं। लोगों को पर्याप्त और सही सूचनाएं, जानकारियां दी जानी जरूरी हैं।

स्वैच्छिक संगठनों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लोगों की भागीदारी और उनको प्रेरित करने की सामर्थ्य कितनी ज्यादा है। इन संस्थाओं के द्वारा इस बीमारी से निपटने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना, निर्धनों की मदद, उन्हें जागरूक करना, चिकित्सा राहत एवं सामान्य जन उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य का उन्नयन किया जाना चाहिए। जब इतने व्यापक स्तर पर लोग महामारी से पीड़ित हों तो चिकित्सकीय प्रणाली पर पूर्ण निर्भरता असफल होती है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता उतनी ही महत्त्वपूर्ण हो जाती है जितनी कि चिकित्सकीय सेवा की। इस तरह के वास्तविक प्रयासों से पीड़ितों की सहायता करने के अलावा उनके बच्चों, परिवार और अन्य आश्रित लोगों की सहायता की जा सकती है जो एकाकीपन और सामाजिक भेदभाव के शिकार हो जाते हैं।

महामारी से के दुश्चक्र से निकलने में बचाव कार्यक्रम भी काफी अहम हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय और न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव द्वारा बनाई गई ग्लोबल हेल्थ सिक्युरिटी (जीएचएस) रिपोर्ट में यह बताया गया कि संपूर्ण विश्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मौलिक रूप से बहुत कमजोर है। कोई भी देश वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है और सभी देशों में यह कोरोना वायरस महामारी गंभीर चुनौती के रूप में सामने आई है। भारत के संदर्भ में देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों को इस संक्रमण से लड़ने के लिए ठोस और कारगर उपायों के बारे में सोचने की जरूरत है। समस्या अभी यह है कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है और इसकी दवा या टीका कब तक तैयार होगा, यह भी कोई नहीं जानता। ऐसे में बचाव के उपाय ही कारगर हो सकते हैं। महामारी के फैलाव को रोकने और इस पर काबू पाने के लिए लोगों के व्यवहार में परिवर्तन, उनको जागरूक तथा शिक्षित करने की आवश्यक है। जनभागीदारी और जनसर्थन से कई प्रभावी कदम भी केंद्र और राज्य सरकारें उठा रही हैं। इसके प्रमुख उपाय के रूप में सामाजिक दूरी का उपाय बहुत कारगर है। वायरस की प्रकृति और उसके फैलने के तरीकों का जो अध्ययन किया गया है, उससे यह सामने आया है कि दो लोगों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी जरूरी है। जिन लोगों को खांसी, जुकाम और बुखार जैसी शिकायतें हैं, उनमें इसके लक्षण होने की संभावना हो सकती है। इसलिए छींकते, खांसते समय सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है,ताकि सामने वाले तक वायरस न पहुंच पाए। हालांकि प्रचार माध्यमों के जरिए इस बारे में लोगों को तरह-तरह से संदेश दिए गए हैं। लेकिन फिर भी समस्या तेजी से बढ़ रही है, जो बड़े खतरे की ओर इशारा करती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि राज्यों को जो कानूनी शक्तियां दी गई हैं, चाहे वह महामारी एक्ट हो या आपदा प्रबंधन कानून हो, सीआरपीसी के तहत उनके द्वारा निर्णायक कदम सबकी सहमति से समाज को साथ लेकर उठाए जाएं। साथ ही साथ बाजारों के समय को नियंत्रित किया जाए, सार्वजनिक यातायात के संसाधनों में कमी की जाए। ये कुछ ऐसे जरूरी कदम हैं जो संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी हैं और सबसे ज्यादा जरूरत इनका पालन सुनिश्चित कराना है। यह काम समाज, सरकार और अन्य सभी वर्गों के समर्थन से ही संभव है। कोविड 19 के व्यापक प्रसार की स्थिति ने विश्व के सभी देशों को ऐसी प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए रणनीति तैयार करने, स्वास्थ्य और आपातकालीन बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में सोचने के लिए बाध्य किया है। विश्व के ज्यादातर देशों को स्कैंडिनेवियाई देशों जिनमें डेनमार्क, नार्वे और स्वीडन प्रमुख हैं, की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है। इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, न्यूनतम मजदूरी सुरक्षा योजना, पेंशन, नागरिकों की जीवन प्रत्याशा आदि शामिल हैं। विश्व के शक्तिशाली देशों को हथियार और परमाणु शक्ति संपन्न बनने के बजाय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बल देना चाहिए, जिससे देश के नागरिकों का जीवन खुशहाल बनेगा।

बहरहाल अभी भारत की जो स्थिति दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास विकसित देशों की तरह संसाधन नहीं हैं। कोरोना की जांच में इस्तेमाल होने वाले किट की भारी कमी की वजह से ही संक्रमण ग्रस्त मरीजों का पता लगाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण कोरिया जैसा छोटा-सा देश लाखों लोगों की जांच कर चुका, जबकि भारत में इस तरह के सबसे जरूरी कदम का अभाव देखने को मिला। ऐसी सूरत में देश के नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी देशवासी इस भयावह प्रकोप से बचने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे बचाव संबंधी कदमों और उपायों की उपेक्षा नहीं करेंगे।

इस युद्ध को 'सरहद' से नहीं, घर से जीतें

कोयल पुरी रिनचैट

फ्रैंड सैनीटाइजर युद्ध का हथियार बन चुके हैं। फ्रांस में सबसे बड़े लग्जरी समूह एल.वी.एम.एच. ने अपनी परफ्यूम फैक्टरियों में से निर्मित सैनीटाइजरों को बहुतायत मात्रा में बनवाकर सरकार तथा अस्पतालों को निःशुल्क बांट दिया। यह ऐसे वक्त में किया गया है जबकि फ्रांस अन्य देशों की तरह कोरोना वायरस के युद्ध से लड़ रहा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रां ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया और घोषणा की कि सभी स्कूल, विश्वविद्यालय अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए जाएं। उनके इस आदेश का सख्ती से पालन किया गया मगर पूरे फ्रांस भर में बच्चे खुशी से झूम उठे। यहां पर पूरे देशवासी एक-दूसरे से कट कर रह गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह कोई बंदी गृह है। लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं और जब वे उदास होते हैं तो अपने दोस्तों को घर में बुला लेते हैं। रोजाना जिम जाने वाले लोग अपने घर पर ही वर्कआऊट कर रहे हैं और ट्रेनर को घर पर ही बुला रहे हैं। कोविड-19 जैसे युद्ध को सीमाओं से नहीं, घर से ही लड़ा जा रहा है। ऐसे युद्ध को लडने के लिए आपके पास युद्ध सामग्री होने की जरूरत नहीं मगर यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सरकार के आदेश को मानें। राष्ट्रपति की स्पीच सुनने के लिए सभी परिवार टी.वी. लगाकर बैठ गए। उनका संदेश 35 मिलियन लोगों ने सुना। मुझे उन दिनों की याद आ गई जब सारा परिवार टी.वी. के आगे बैठ जाता था क्योंकि उनके पास दूसरा सूचना का कोई साधन नहीं था। मैक्रां ने हालांकि मास्क पहने की जरूरत को सिरे से नकार दिया (क्योंकि वहां पर ये काफी मात्रा में उपलब्ध नहीं) उन्होंने हमारे संग एक युद्ध के सेनापति की तरह बात की जोकि युद्ध भूमि में खड़ा हो। विंस्टन चर्चिल को द्वितीय विश्वयुद्ध और बुश को 9/11 के दौरान भाषण करते देखा। मैक्रां ने घोषणा की कि हम युद्ध की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए उन्होंने बलिदान देने के लिए लोगों को कहा, वहीं सौहार्द बनाए रखने के लिए भी कहा। सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही कि इस वायरस को किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्या करें और क्या न करें। सभी व्यवसाय बंद कर दिए। बिजली, गैस तथा पानी के बिलों को निलंबित कर दिया गया। एक आर्मी कैम्प अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की गई। उसके बाद उन्होंने सबसे डरावनी घोषणा की। उन्होंने कहा कि घरों के अंदर रहें, नहीं तो आपको सजा मिलेगी।

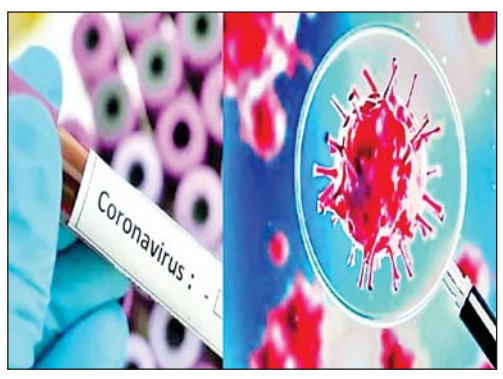

भारतीय होने के नाते मैं जल्दी ही इस वायरस तथा युद्ध के लिए आतंकित नहीं होती मगर मैं नियमों को जरूर मानती। एक जमाखोर के नाते मैं सबसे बड़ी जमाखोरी टायलट पेपर की नहीं करती क्योंकि भारतीय होने के नाते मेरे पास कई विकल्प हैं मगर खाने-पीने की चीजें कम से कम रखनी चाहिएं। कुछ चैनलों ने सबके लिए फ्री केबल देने का फैसला किया। सुपर मार्कीटों ने डिलीवरी चार्ज लेने से मना कर दिया। स्कूलों ने ई-लर्निंग स्थापित की तथा एल.वी.एम.एच. ने इस युद्ध से लडने के तौर पर निःशुल्क सैनीटाइजर सरकार को तथा अस्पतालों को बांटे। कम्पनी ने युद्ध स्तर पर इसका निर्माण किया।

इस युद्ध को जीतने के लिए हमें अपने घर से शुरूआत करनी होगी। आप घर बैठे फ्री टी.वी. देखें, सरकार की ओर से बांटे गए खाने को खाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको सैनीटाइज करें तथा अपने घरों में बैठे रहें। हालांकि घूमने-फिरने वाले व्यक्तियों के लिए एक परिधि में बैठना मुश्किल होता है। पैरिस के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं किस्मत वाली हूं कि मैं एक बड़े अपार्टमैंट में रहती हूं। मैंने अपनी नैनी को कह रखा है कि वह अपने घर पर ही रहें, जब तक कि सरकार अपने आदेश को बदल न डाले।

डॉ लोहिया के 'निराशा के कर्तव्य'

कृष्ण प्रताप सिंह

समाजवादी चिंतक डॉ राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें याद करने के साथ इस विडंबना को भी याद करना जरूरी है कि आज की तारीख में खुद को उनका वारिस कहनेवाली पार्टियां और नेता गहन वैचारिक निराशा से गुजर कर भी उनके सिखाये %निराशा के कर्तव्यों% को निभाने को तैयार नहीं हैं, जो डॉ लोहिया ने 23 जून, 1962 को नैनीताल में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया था. याद करें, वह ऐसा दौर था, जब फरवरी, 1962 में संपन्न हुए लोकसभा के तीसरे चुनाव में समाजवादियों द्वारा जगायी गयी परिवर्तन की तमाम उम्मीदों के विपरीत प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 12 और सोशलिस्ट पार्टी को छह सीटें ही मिल पायी थीं. इससे समाजवादी निराश थे. इसलिए भी कि स्वतंत्र पार्टी ने अकेले ही इन दोनों के बराबर 18 सीटें जीत ली थीं, जबकि 14 सीटें भारतीय जनसंघ के खाते में गयी थीं.भाकपा ने 29 सीटें जीत कर अपना पुराना प्रदर्शन सुधार लिया था. यानी समाजवादियों के समक्ष लगभग आज जैसा ही अप्रासंगिक हो जाने का खतरा था. जब समाजवाद महज संविधान की प्रस्तावना में रह गया है, तब डॉ लोहिया ने न सिर्फ इन निराशा के कारणों की पड़ताल की थी, बल्कि उसे पार करने के कई जरूरी कर्तव्य भी बताये थे. उन्होंने कहा था कि देश की

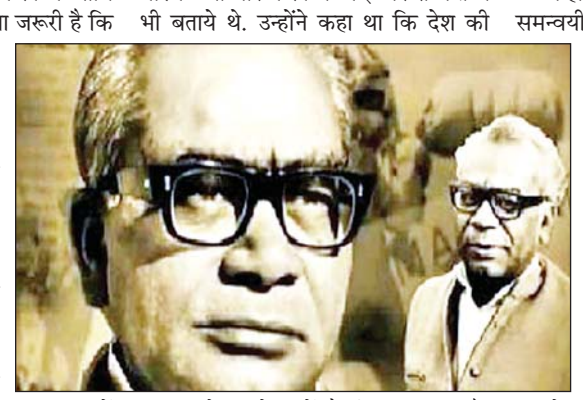

जनता को अपने हकों के लिए लड़ना और उसकी कीमत चुकाना सिखाएं.

बगैर इसके यह निराशा हमारा पीछा नहीं छोड़नेवाली, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में, पिछले पंद्रह सौ वर्षों में हिंदुस्तान की जनता ने एक बार भी किसी अंदरूनी जालिम के खिलाफ विद्रोह नहीं किया. एक राजा, जो आंतरिक तौर पर देश का रहनुमा बन चुका है, लेकिन जालिम है, उसके खिलाफ जनता नहीं खड़ी हुई. ऐसा विद्रोह नहीं हुआ, जिसमें हजारों-लाखों लोग हिस्सा लेते हैं. इस पंद्रह सौ वर्षों के अभ्यास के कारण झुकना हिंदुस्तान की जनता की हड्डी और खून का हिस्सा बन गया है. इस झुकने को हमारे देश में बड़ा सुंदर नाम दिया जाता है.

कहा जाता है कि हमारा देश तो बड़ा समन्वयी है, हम सभी अच्छी बातों को अपने में मिला लिया करते हैं. उन्होंने इस समन्वय के दो प्रकार बताकर उसके खतरे गिनाये थे= %एक दास का समन्वय और दूसरा स्वामी का समन्वय. स्वामी या ताकतवर देश या ताकतवर लोग समन्वय करते हैं, तो परखते हैं कि कौन सी पराई चीज अच्छी है, उसको किस रूप में अपना लेने से उनकी शक्ति बढ़ेगी और तब वे उसे अपनाते हैं. लेकिन नौकर या दास या गुलाम परखता नहीं है.उसके सामने जो भी नयी परायी चीज आती है, अगर वह ताकतवर है, तो वह उसको अपना लेता है. यह झख मार कर अपनाना हुआ. अपने देश में पिछले पंद्रह सौ वर्षों से जो समन्वय चला आ रहा है, वह ज्यादातर इसी ढंग का है. इसका नतीजा यह हुआ है कि आदमी अपनी चीजों के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए मरने-मिटने के लिए ज्यादा तैयार नहीं रहता. वह झुक जाता है और उसमें स्थिरता के लिए भी बड़ी इच्छा पैदा हो जाती है।